(1)	(2)	(3)	(4)
Sikkim	412.91	2172	2215
Tamil Nadu	47248.37	191801	202187
Tripura	593.42	3428	3877
Uttar Pradesh	57958.38	559309	419722
West Bengal	15757.03	193448	111215
A & N Islands	107.28	959	101
D & N Haveli	36.37	673	230
Daman & Diu	32.36	322	233
Lakshadweep	17.12	205	115
Pondicherry	83.66	932	244
TOTAL :	*378460.31	3021898	2620660

*Provisional

मधुबनी जिले में सामाजिक और शैक्षणिक विकास केन्द्र के विरुद्ध कार्यवाही

2439. **श्री राम देव भण्डारी :** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** 20 मार्च, 1997 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 2822 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपार्ट में बिहार के मधुबनी जिला स्थित सामाजिक और शैक्षणिक विकास केन्द्र पथराही, झंझारपुर (रेलवे स्टेशन) के विरुद्ध आगे धन बन्द करने के अतिरिक्त और क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या कोष के दुरूपयोग के मामल आगे धन देना बन्द कर देना ही पूर्ण कार्यवाही है;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में धन वसूल करने एफ. आई. आर. दर्ज कराने और काली सूची में डाल देने जैसी कार्यवाही शुरू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या एक संयुक्त दल द्वारा मूल्यांकन किये जाने के पश्चात् 9.74 लाख रुपये की वसूली की कार्यवाही के मामले में विलम्ब करने में कपार्ट के कुछ अधिकारियों का हाथ है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में की जा रही कार्यवाही की स्थिति क्या है और अन्य ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री (श्री किंजरापू येरन्नायडु) : (क) से (ग) : आगे सहायता बन्द करना एक अंतरिम उपाय है । कपार्ट की वर्तमान नीति के अनुसार स्वैच्छिक संगठन को नोटिस जारी किया जाता है जिसमें यह कहा जाता है कि नोटिस जारी करने की तारीख के एक माह के अन्दर कारण बताएं कि क्यों न उसे काली सूची में डाल दिया जाए। नोटिस की अवधि समाप्त होने पर मामले को या तो बन्द कर दिया जाता है अथवा काली सूची में डालने के लिए निगरानी और मूल्यांकन संबंध राष्ट्रीय स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है यदि राष्ट्रीय स्थायी समिति काली सूची में डालने का आदेश देती है तो स्वैच्छिक संगठन को दी गई सहायता वापस ले ली जाती है और संबंधित जिले के पुलिस अधिक्षक के पास काली सूची में डाले गए स्वैच्छिक संगठन के कर्मचारियों के विरुद्ध धोखाधड़ी आपराधिक न्यासभंग और सार्वजनिक निधियों के दुर्विनियोज के लिए आपराधिक कार्यवाही प्रारम्भ कर

के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है । वर्तमान मामले में कपार्ट द्वारा बिहार के मधुबनी जिला स्थित सामाजिक और शैक्षणिक विकास केन्द्र, पथराही झंझारपुर को 8.7.1997 को ऐसा ही, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है । अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । इसलिए, मामले को राष्ट्रीय स्थायी समिति के विचार के लिए भेजा जा रहा है ।

(घ) और (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठते क्योंकि कपार्ट की वर्तमान नीति के अनुसार कार्रवाई की जा रही है ।

Development of women and children in Bihar

2440. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government have prepared any action plan for the development of women and children in rural areas of Bihar;

(b) if so, the details thereof;

(c) the funds released to the State during the last three years, year-wise and results achieved during the said period; and

(d) the funds earmarked during 1997-98 for the purpose?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) and (b) No, Sir. This Ministry does not prepare any specific action plan for the development of women and children in the rural areas of any State including Bihar. Under DWCRA (Development of Women and Children in Rural Areas), year-wise target of formation of DWCRA groups is indicated to the respective State Governments for necessary action.

(c) Information is given below.

Year	Central Release (Rs. in lakhs)	Target (No. of groups)	Achievement	Membership (all members are women)
1994-95	212.20	1051	900	13386
1995-96	225 00	3042	2697	37570
1996-97	332 75	3042	2415	33661

(d) Rs. 380.25 lakhs have been earmarked as central allocation during the year 1997-98 for formation of 3042 groups.

Rural development scam in Rajasthan

2441. SHRI S. M. KRISHNA: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Prime Minister has received any letter/representation from Mazdoor Kisan Shakti Sangathan, Rajasthan urging for CBI probe into rural development scame of the State; if so, the details thereof;

(b) whether the requisite has been done for CBI investigation;

(c) the amount released to the State under rural development scheme during the last three years, year-wise; and

(d) whether Government have at any stage during last three years received the performance of the State on the rural development scheme taken up by Central Assistance, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI K. YERRANNAIDU): (a) and (b) No